एएफआर

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>एआरबीएपी नंबर 10/2023</u>

1- बल्क ट्रेडिंग एस.ए. का कार्यालय पियाज़ा मोलिनो नुओवो 17 लूगानो सीएच में है- 6900, स्विट्ज़रलैंड, अपने अधिकृत प्रतिनिधि, श्री अल्बर्टो रावानो के माध्यम से इसलिए। पिएत्रो , उम्र लगभग 73 वर्ष, पियाज़ा नोलिनो नुओवो 17 में कार्यालय रखते हुए 6900 लूगानो, स्विट्जरलैंड

---- याचिकाकर्ता

बनाम

महेंद्र स्पंज एंड पावर लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय ए ब्लॉक, 2 में है फ्लोर, मारुति बिजनेस पार्क, धुप्पर पंप के पास, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़. 492001

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- उत्तरदाता

<u>एआरबीएपी नंबर 9/2023</u>

1 - बल्क ट्रेडिंग एस.ए. का कार्यालय पियाज़ा मोलिनो नुओवो 17 लूगानो सी एच में है - 6900, स्विट्ज़रलैंड, अपने अधिकृत प्रतिनिधि, श्री अल्बर्टो रावानो के माध्यम से पुत्र पिएत्रो , उम्र लगभग 73 वर्ष, पियाज़ा नोलिनो नुओवो 17, 6900 में कार्यालय है
लूगानो, स्विट्ज़रलैंड।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - महेंद्र स्पंज एंड पावर लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय एक ब्लॉक में है, दूसरी मंजिल, मारुति बिजनेस पार्क, धुप्पर पंप के पास, जी.ई. रोड, रायपुर,छत्तीसगढ़- 492001.

---- उत्तरदाता

आवेदक के लिए : सुश्री फ़ेरेस्टे डी. सेठना, हर्षमंदर की अधिवक्ता रस्तोगी, श्री अमिय पंत और श्री मोहित तिवारी,अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए : श्री आशीष आनंद बरनाड, श्री आशीष के अधिवक्ता मित्तल और श्री मेहल जेठानी, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी

बोर्ड पर आदेश

07/11/2024

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. ये दो मध्यस्थता आवेदन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 के अध्याय 1, भाग-II की धारा 47, 48 और 49 के तहत सीपीसी के आदेश XXI और धारा 151 के साथ दिनांक 11.8.2021 के अंग्रेजी मध्यस्थता पुरस्कार और दिनांक 27.3.2023 के लागत पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए दायर किए गए हैं।

2. निर्विवाद रूप से, 6.3.2020 को, 50,000 मीट्रिक टन +/- 10% कोयले की बिक्री के लिए एक अनुबंध (अनुबंध) पार्टियों के बीच ई-मेल के आदान-प्रदान के माध्यम से दर्ज किया गया था , जिसमें मानक कोयला व्यापार समझौता संस्करण 8, सामान्य नियम और शर्तें (ScoTA) शामिल थीं। इसके अलावा, प्रतिवादी/निर्णय देनदार को डिलीवरी अवधि शुरू होने से 10 दिन पहले यानी 31.3.2020 से पहले क्रेडिट का एक पत्र (एलसी) खोलने के लिए बाध्य किया गया था। प्रतिवादी/निर्णय-देनदार उक्त तारीख तक एलसी खोलने में विफल रहा। ऐसी विफलता एक डिफ़ॉल्ट की घटना के बराबर थी , जो पुरस्कार-धारक/आवेदक को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार देती है। तत्पश्चात, एक विवाद को संदर्भित किया गया तथा आवेदक के पक्ष में मध्यस्थ निर्णय और लागत निर्णय पारित किया गया। प्रतिवादी/डिक्री-धारक ने अंग्रेजी मध्यस्थता निर्णय, 1996 के अंतर्गत

अपील के माध्यम से उपरोक्त निर्णयों को चुनौती दी तथा दोनों निर्णय अंतिम हो चुके हैं। योग्यता निर्णय और लागत निर्णय यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होते हैं तथा इस प्रकार , वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विदेशी निर्णय (मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम, 1961) की धारा 2 के खंड (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना दिनांक 25.10.1976 द्वारा शासित होते हैं, तथा इसे भारत के राजपत्र में 13.11.1976 को प्रकाशित किया गया है। चूंकि प्रतिवादी/निर्णय-देनदार की संपत्ति छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए उक्त विदेशी निर्णय को मान्यता देने के लिए ये दोनों आवेदन दायर किए गए हैं।

3. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष आनंद बरनाड ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 (संक्षेप में "अधिनियम, 1996") की धारा 48 के मद्देनजर उक्त विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार किया जा सकता है क्योंकि उक्त पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा कोविड-19 महामारी की असाधारण स्थिति को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (संक्षेप में "अधिनियम, 2005") की धारा 10(2)(एल) के तहत विभिन्न अधिसूचनाएं/परिपत्र जारी किए गए हैं। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता गृह सचिव द्वारा जारी पत्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश, दोनों दिनांक 24.3.2020 का संदर्भ देंगे, जिसमें इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के क्रम संख्या 4 में निर्देश दिया गया है कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाना चाहिए , हालांकि बैंकों, बीमा कार्यालयों और एटीएम के लिए एक अपवाद (क्रम संख्या 4 बी में) था। वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि उक्त अपवाद के अलावा क्रम संख्या 13 में एक और शर्त थी, जिसके तहत निर्देश दिया गया है कि संगठनों /नियोक्ताओं को कोविड -19 वायरस के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खिलाफ आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित करनी चाहिए और साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर सलाह के अनुसार सामाजिक दूरी के उपाय भी करने चाहिए। उन्होंने आगे क्रम संख्या 13 का हवाला दिया। उक्त दिशा-निर्देशों की क्रम संख्या 17, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि इन रोकथाम उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के अलावा अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी असाधारण स्थिति में, प्रतिवादी/निर्णय-देनदार की आवाजाही उस अवधि के दौरान प्रतिबंधित हो गई और इसके अलावा, बैंक से एलसी प्राप्त करना आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की तरह आवश्यक नहीं था। उन्होंने आगे उक्त दिशा-निर्देशों की क्रम संख्या 15 की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसके तहत सभी प्रवर्तन अधिकारियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की सीमा तक छूट दी गई थी। इसलिए, प्रतिवादी/निर्णय-देनदार ने ऐसी असाधारण स्थिति में ऋण पत्र प्राप्त नहीं किया, हालांकि, विद्वान मध्यस्थों ने प्रस्तुत किए गए उक्त प्रस्तुतिकरण पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया और उक्त आपत्ति को खारिज कर दिया और आवेदक के पक्ष में पुरस्कार पारित किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त पुरस्कार के पैरा 50 में उठाई गई आपत्तियों पर प्रकाश डाला, जिसमें विद्वान मध्यस्थों ने देखा है कि 'भारत में होने वाली एकमात्र घटना 1 अप्रैल से पहले बिक्री अनुबंध द्वारा आवश्यक एलसी का उद्घाटन था। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि हमने जो सबूत देखे हैं - या, अधिक विशेष रूप से, नहीं देखे हैं - कि महामारी ने ऐसी घटना को असंभव बना दिया है। इसके अलावा, यदि ऐसी कोई एफएम घटना होती, तो हम इसे बिक्री अनुबंध में निर्धारित एफएम की परिभाषा से अलग मानते, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 47 में बताया गया है - पैराग्राफ ए के तहत "समझौते के तहत कोई भी भुगतान करने का दायित्व"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ बनाम एलीमेंटा एस.ए. (2020) 19 एससीसी 260** (पैरा 69) के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करेंगे, जिसमें यह देखा गया था कि नेफेड आपूर्ति करने में असमर्थ था क्योंकि उसके पास 1980-81 के मौसम में आपूर्ति करने के लिए कोई अनुमति नहीं थी , उसे सरकार की अनुमति की आवश्यकता थी। मामला ऐसा है जो भारत की मौलिक नीति से संबंधित है और पार्टियों को इसकी जानकारी थी, और उन्होंने अनुबंध किया था कि खंड 14 में प्रदान की गई ऐसी आपात स्थिति में, आपूर्ति नहीं की जा सकने के लिए समझौता रद्द कर दिया जाएगा। पिछले वर्ष की वस्तु को अगले सीजन में निर्यात करने की कोई अनुमति नहीं थी और फिर सरकार ने नेफेड को आपूर्ति करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसमें यह माना गया कि इस तरह के पुरस्कार को लागू करना भारत की मौलिक सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने **एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, (2015) 3 एससीसी 49** के मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया और इसके पैरा 27 का संदर्भ दिया, जो इस प्रकार है:

> भारतीय कानून की मौलिक नीति
>
> **27.** सॉ पाइप्स (2003) 5 एससीसी 705, एआईआर 2003 एससी 2629 निर्णय में निहित प्रत्येक शीर्षक पर आते हुए, हम सबसे पहले "भारतीय कानून की मौलिक नीति" शीर्षक पर विचार करेंगे। रेनुसागर 1994 सप्लीमेंट (1) एससीसी 644 निर्णय से यह पहले ही देखा जा चुका है कि विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन और भारत में वरिष्ठ उच्च न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना करना भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत माना जाएगा। इसमें यह भी

जोड़ा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना का बाध्यकारी प्रभाव भारतीय कानून की मौलिक नीति का समान रूप से उल्लंघन होगा।

6. अंत में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था और एसएलडब्ल्यू (सी) संख्या 3/2020 में सीमा को बढ़ा दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह की महामारी के कारण; प्रतिवादी विषय अवधि के दौरान एलसी प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में अधिनियम 2005 के तहत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा था। हालाँकि, इस पहलू को विद्वान मध्यस्थों द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है। इसलिए, दोनों आरोपित पुरस्कार टिकाऊ नहीं हैं, इसलिए, वह उक्त पुरस्कारों के प्रवर्तन से इनकार करने की प्रार्थना करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उपर्युक्त प्रस्तुतियों का उत्तर देते हुए आवेदक /पुरस्कार-धारक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री फेरेस्थे डी. सेठना ने प्रस्तुत किया कि विषय अधिसूचना में ही बैंकों के लिए अपवाद है और उक्त आधार प्रतिवादी/निर्णय ऋणी द्वारा विद्वान मध्यस्थों के समक्ष लिया गया है। पुरस्कार के पैरा 46 से आगे, विद्वान मध्यस्थों ने उक्त पहलू से निपटा है और उन्होंने पैरा 49 में स्पष्ट रूप से देखा है कि बैंक और शिपिंग अपवादित उद्योग हैं और वे लॉकडाउन नियमों के अधीन नहीं थे। यदि कोविड-19 महामारी के कारण किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना या निराशा की घटना हुई थी, तो खरीदार द्वारा इसके विपरीत सबूत पेश किए जाने चाहिए थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान भी, कुछ आवश्यकताओं के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा पास और परमिट जारी किए गए थे। हालांकि, इस संबंध में प्रतिवादी/निर्णय ऋणी द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए, विद्वान मध्यस्थों ने पैरा 50 में इस तरह की आपत्ति को यह देखते

हुए सही रूप से नजरअंदाज कर दिया है कि ऐसी स्थिति में , प्रतिवादी के लिए एलसी प्राप्त करना असंभव नहीं था और आवेदक के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि प्रतिवादी या उसके कर्मचारी के लिए ऋण पत्र खोलने के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक जाना भी आवश्यक नहीं था क्योंकि एलसी खोलने के लिए किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। अंत में, आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों पुरस्कार अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि निर्णयों की एक श्रृंखला में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि न्यायालय के समक्ष जांच का दायरा सीमित है जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है और यह अधिनियम, 1996 की धारा 48 में उल्लिखित आधारों तक सीमित है। वह **श्री लाल महल लिमिटेड बनाम प्रोगेटो ग्रेनो स्पा** के मामले पर भरोसा करेगी, जिसकी रिपोर्ट **(2014) 2 एससीसी 433** में की गई है और पैरा 45 का संदर्भ देगी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि अधिनियम , 1996 की धारा 48 पुरस्कार प्रवर्तन चरण में विदेशी पुरस्कार पर "दूसरी नज़र" डालने का अवसर नहीं देती है। उक्त निर्णय का पैरा 45 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> 45. इसके अलावा, 1996 अधिनियम की धारा-48 विदेशी पुरस्कार पर पुरस्कार प्रवर्तन चरण में "दूसरी नज़र" डालने का अवसर नहीं देती है। धारा 48 के तहत जांच का दायरा योग्यता के आधार पर विदेशी पुरस्कार की समीक्षा की अनुमति नहीं देता है। विदेशी मध्यस्थता के दौरान प्रक्रियात्मक दोष (जैसे अस्वीकार्य साक्ष्य पर विचार करना या साक्ष्य की अनदेखी करना/अस्वीकार करना जो बाध्यकारी प्रकृति का हो सकता है) सार्वजनिक नीति के आधार पर किसी पुरस्कार को लागू करने से छूट नहीं देते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **सैंगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), (2019) 15 एससीसी 131** के मामले पर भरोसा करेंगे, जिसमें विदेशी पुरस्कार को चुनौती देने के संबंध में पहलू को पैरा 44 से 48 और पैरा 69 में स्पष्ट रूप से निपटाया गया था, जो इस प्रकार है:

> **44.** रेनूसागर (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 ["विदेशी पुरस्कार अधिनियम"] की धारा 7 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को चुनौती दी थी। विदेशी पुरस्कार अधिनियम को तब से 1996 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है। हालाँकि, यह देखते हुए कि विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 में ऐसे आधार शामिल थे जो विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 ["न्यूयॉर्क कन्वेंशन"] के अनुच्छेद V से उधार लिए गए थे, जो लगभग 1996 के अधिनियम की धारा 34 और 48 के समान ही हैं, उक्त निर्णय न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है जब बात विदेशी पुरस्कारों या भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की आती है, धारा 34 और 48 के तहत प्रवर्तन की चुनौती/अस्वीकृति के आधार क्रमशः समान हैं।
>
> **45.** न्यूयॉर्क कन्वेंशन का संदर्भ देने के बाद, इस न्यायालय ने धारा 34/48 के तहत आधारों की जांच के दायरे को रेखांकित किया (विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 के तहत आधारों के समतुल्य, जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया था), और माना:-
>
> "34. 1927 के जिनेवा कन्वेंशन के तहत, किसी विदेशी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मध्यस्थ पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन प्राप्त करने के लिए, अनुच्छेद I के खंड (ए) से (ई) की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना था और अनुच्छेद II में, यह निर्धारित किया गया था कि भले ही अनुच्छेद I में निर्धारित शर्तें पूरी हो गई हों, लेकिन पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार कर दिया जाएगा यदि न्यायालय खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित मामलों के संबंध में संतुष्ट था। विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर लागू होने वाले सिद्धांत मूल रूप से अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा सामान्य कानून में अपनाए गए सिद्धांतों के समान हैं। (देखें: डाइसी और मॉरिस, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़, 11 संस्करण, खंड I, पृष्ठ 578)। हालाँकि, यह महसूस किया गया कि जिनेवा कन्वेंशन में कुछ दोष थे जो मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के त्वरित निपटान में बाधा डालते थे। न्यूयॉर्क कन्वेंशन विदेशी पुरस्कारों की मान्यता प्राप्त करने और उन्हें लागू करने का एक अधिक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करके उक्त दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत जिस पक्ष के खिलाफ पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है, वह अनुच्छेद V के खंड (1) के उप-खंड (ए) से (ई) में निर्धारित आधारों पर विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन पर आपत्ति कर सकता है और न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, अनुच्छेद V के खंड (2) के उप-खंड (ए) और (बी) में निर्धारित दो अतिरिक्त कारणों से विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार कर सकता है। खंड (1) के उप-खंड (ए) से (ई) और अनुच्छेद V के खंड (2) के उप-खंड (ए) और (बी) में निर्धारित कोई भी आधार योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती नहीं देता है।

35. अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग ने अपने ग्रंथ द

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन ऑफ़ 1958: ट्रुवड्र्स ए यूनिफ़ॉर्म ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन में यह विचार व्यक्त किया है:

"यह कन्वेंशन की आम तौर पर स्वीकृत व्याख्या है कि जिस न्यायालय के समक्ष विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन की मांग की जाती है, वह पुरस्कार की योग्यता की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसका मुख्य कारण यह है अनुच्छेद । के खंड (ए) से (ई) की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना था और अनुच्छेद ।। में, यह निर्धारित किया गया था कि भले ही अनुच्छेद । में निर्धारित शर्तें पूरी हो गई हों, लेकिन पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार कर दिया जाएगा यदि न्यायालय खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित मामलों के संबंध में संतुष्ट था। विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर लागू होने वाले सिद्धांत मूल रूप से अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा सामान्य कानून में अपनाए गए सिद्धांतों के समान हैं। (देखें: डाइसी और मॉरिस, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़, 11 संस्करण, खंड ।, पृष्ठ 578)। हालाँकि, यह महसूस किया गया कि जिनेवा कन्वेंशन में कुछ दोष थे जो मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के त्वरित निपटान में बाधा डालते थे। न्यूयॉर्क कन्वेंशन विदेशी पुरस्कारों की मान्यता प्राप्त करने और उन्हें लागू करने का एक अधिक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करके उक्त दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत जिस पक्ष के खिलाफ पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है, वह अनुच्छेद V के खंड (1) के उप-खंड (ए) से (ई) में निर्धारित आधारों पर विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन पर आपत्ति कर सकता है और न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, अनुच्छेद V के खंड (2) के उप-खंड (ए) और (बी) में निर्धारित दो अतिरिक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कारणों से विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार कर सकता है। खंड (1) के उप-खंड (ए) से (ई) और अनुच्छेद V के खंड (2) के उप-खंड (ए) और (बी) में निर्धारित कोई भी आधार योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती नहीं देता है।

35. अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग ने अपने ग्रंथ द न्यू यॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन ऑफ़ 1958: टुवर्ड्स ए यूनिफ़ॉर्म ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन में यह विचार व्यक्त किया है:

"यह कन्वेंशन की आम तौर पर स्वीकृत व्याख्या है कि जिस न्यायालय के समक्ष विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन की मांग की जाती है, वह पुरस्कार की योग्यता की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुच्छेद V में प्रवर्तन से इनकार करने के लिए आधारों की विस्तृत सूची में मध्यस्थ द्वारा तथ्य या कानून में कोई गलती शामिल नहीं है। इसके अलावा, कन्वेंशन के तहत प्रवर्तन न्यायाधीश का कार्य सीमित है। उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नियंत्रण यह सत्यापित करने तक सीमित है कि अनुच्छेद V(1) के इनकार के आधार पर प्रतिवादी की आपत्ति उचित है या नहीं और क्या पुरस्कार का प्रवर्तन उसके देश केकि अनुच्छेद V में प्रवर्तन से इनकार करने के लिए आधारों की विस्तृत सूची में मध्यस्थ द्वारा तथ्य या कानून में कोई गलती शामिल नहीं है। इसके अलावा , कन्वेंशन के तहत प्रवर्तन न्यायाधीश का कार्य सीमित है। उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नियंत्रण यह सत्यापित करने तक सीमित है कि अनुच्छेद V(1) के इनकार के आधार पर प्रतिवादी की आपत्ति उचित है या नहीं और क्या पुरस्कार का प्रवर्तन उसके देश के कानून की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करेगा। इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के सिद्धांत के प्रकाश में देखा जाना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चाहिए कि किसी राष्ट्रीय न्यायालय को मध्यस्थता के सार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। (पृष्ठ 269)

36.इसी तरह एलन रेडफर्न और मार्टिन हंटर ने कहा है:

"न्यूयॉर्क कन्वेंशन किसी ऐसे पुरस्कार की योग्यता पर किसी भी समीक्षा की अनुमति नहीं देता है जिस पर कन्वेंशन लागू होता है और इसलिए, इस संबंध में, यह किसी पुरस्कार की चुनौती को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय कानून की कुछ प्रणालियों के प्रावधानों से अलग है, जहां कानून के बिंदुओं पर न्यायालयों में अपील की अनुमति दी जा सकती है। " (रेडफर्न और हंटर, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का कानून और अभ्यास, 2 संस्करण, पृष्ठ 461.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. इसलिए, हमारी राय में, विदेशी पुरस्कार अधिनियम, 1961 के तहत विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए कार्यवाही में, जिस न्यायालय में पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है, उसके समक्ष जांच का दायरा अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित आधारों तक सीमित है और उक्त कार्यवाही में किसी पक्ष को योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने में सक्षम नहीं बनाता है।

XXX XXX XXX

65. इसका तात्पर्य यह होगा कि धारा 7(1)(बी)(ii) के तहत अनुमेय सार्वजनिक नीति का बचाव संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि 1927 के जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम के अनुच्छेद I(e) के तहत, इस आधार पर मध्यस्थ पुरस्कार के प्रवर्तन पर आपत्ति उठाने की अनुमति है कि पुरस्कार की मान्यता या

प्रवर्तन सार्वजनिक नीति या उस देश के कानून के सिद्धांतों के विपरीत है जिसमें उस पर भरोसा किया जाना है। प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम 1837 की धारा 7(1) में इसी प्रभाव का प्रावधान है , जिसके अनुसार विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन भारत की सार्वजनिक नीति या कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए। चूँकि अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति" उस क्षेत्र को कवर करती है जो उक्त अभिव्यक्ति के बाद आने वाले शब्दों "और भारत के कानून" द्वारा कवर नहीं किया जाता है, केवल कानून का उल्लंघन सार्वजनिक नीति के प्रतिबंध को आकर्षित नहीं करेगा और कानून के उल्लंघन से अधिक कुछ की आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

66. 1958 के न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V(2)(b) और विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7(1)(b)(ii) किसी विदेशी पुरस्कार को इस आधार पर मान्यता देने और लागू करने से इनकार नहीं करते कि यह लागू करने वाले देश के कानून के विपरीत है और चुनौती का आधार केवल मान्यता देने और लागू करने तक सीमित है जो उस देश की सार्वजनिक नीति के विपरीत है जिसमें पुरस्कार लागू किया जाना है। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V(2) (बी) और विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7(1)(बी)(ii) में “सार्वजनिक नीति” अभिव्यक्ति का उपयोग उसी अर्थ में नहीं किया गया है जिस अर्थ में इसका उपयोग 1927 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद I(सी) और 1937 के प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम की धारा 7(1) में किया गया था। इसका मतलब यह होगा कि धारा 7(1)(बी)(ii) में “सार्वजनिक नीति” का उपयोग संकीर्ण अर्थ में किया गया है और सार्वजनिक

> नीति के प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए पुरस्कार के प्रवर्तन में भारत के कानून के उल्लंघन से अधिक कुछ शामिल होना चाहिए। चूंकि विदेशी पुरस्कार अधिनियम उन विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित है जो निजी अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों द्वारा शासित हैं , इसलिए विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7(1)(बी)(ii) में अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति" को आवश्यक रूप से इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि सार्वजनिक नीति के सिद्धांत को निजी अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में लागू किया जाता है। उक्त मानदंडों को लागू करते हुए, यह माना जाना चाहिए कि किसी विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा कि यह सार्वजनिक नीति के विपरीत है यदि ऐसा प्रवर्तन (i) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (ii) भारत के हितों; या (iii) न्याय या नैतिकता के विपरीत होगा।
>
> (जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. इस निर्णय को निगेल ब्लैकबी, कॉन्स्टेंटाइन पार्टसाइड्स, एलन रेडफर्न और मार्टिन हंटर (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पांचवां संस्करण, 2009) ["रेडफर्न और हंटर"] द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर रेडफर्न और हंटर में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था:

> "11.56. सबसे पहले, न्यूयॉर्क कन्वेंशन किसी ऐसे पुरस्कार की योग्यता पर किसी भी समीक्षा की अनुमति नहीं देता है जिस पर कन्वेंशन लागू होता है। [यह कथन, जो इस पुस्तक के पिछले संस्करण में दिया गया था , को बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। .. न्यायालय ने कहा कि उसकी राय में 'जिस न्यायालय में पुरस्कार

लागू करने की मांग की जाती है , उसके समक्ष जांच का दायरा [अधिनियम में उल्लिखित आधारों तक] सीमित है और उक्त कार्यवाही में किसी पक्ष को योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने में सक्षम नहीं बनाता है ']। न ही मॉडल कानून ऐसा करता है।"

47. यही विषय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर मानक पाठ्यपुस्तकों में भी दोहराया गया है। इस प्रकार , गैरी बी. बोर्न (वोल्टर्स क्लूवर, द्वितीय संस्करण, 2014) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में ["गैरी बोर्न"], विद्वान लेखक इस मामले के इस पहलू से इस प्रकार निपटते हैं:

"[12] मान्यता कार्यवाही में विदेशी या गैर-घरेलू पुरस्कारों की योग्यता की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं

यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का लगभग पवित्र सिद्धांत है कि न्यायालय मान्यता कार्यवाही में विदेशी या गैर-घरेलू मध्यस्थ पुरस्कारों में निहित मध्यस्थों के निर्णयों के सार की समीक्षा नहीं करेंगे। वस्तुतः प्रत्येक प्राधिकरण इस नियम को स्वीकार करता है और वस्तुतः कोई भी यह सुझाव नहीं देता है कि इस सिद्धांत को छोड़ दिया जाना चाहिए। जब राष्ट्रीय न्यायालय पुरस्कारों की योग्यता की समीक्षा करते हैं , तो वे योग्यता की समीक्षा को उचित ठहराने के बजाय अपनी कार्रवाई को सार्वजनिक नीति के अनुप्रयोग, अधिकार की अधिकता या किसी अन्य अनुच्छेद V अपवाद के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं।

[ए] न्यूयॉर्क और अंतर-अमेरिकी सम्मेलनों के तहत पुरस्कारों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं

न तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन और न ही इंटर-अमेरिकन कन्वेंशन में कोई अपवाद है जो किसी पुरस्कार को लागू न करने की अनुमति देता है, केवल इसलिए कि मध्यस्थों ने पक्षों के विवाद के सार पर अपना निर्णय गलत या बहुत गलत लिया। यह कन्वेंशन की भाषा से काफी हद तक स्पष्ट है, जो विदेशी और गैर-घरेलू पुरस्कारों को मान्यता देने से इनकार करने के लिए विशेष आधारों की अनुच्छेद V की विस्तृत सूची में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

योग्यता की समीक्षा की संभावना का कोई संदर्भ नहीं देता है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के प्रारूपण इतिहास में मान्यता कार्यवाही में मध्यस्थ पुरस्कार की योग्यता पर पुनर्विचार करने के लिए किसी भी प्राधिकरण का कोई संकेत नहीं है।

इसी तरह, मध्यस्थ के निर्णय की योग्यता की समीक्षा के खिलाफ निषेध कन्वेंशन की व्याख्या करने वाले राष्ट्रीय न्यायालय प्राधिकरण के सबसे बुनियादी स्तंभों में से एक है। इस निषेध की बार-बार और समान रूप से राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा पुष्टि की गई है, दोनों सामान्य कानून और नागरिक कानून क्षेत्राधिकारों में। सीधे शब्दों में कहें तो: "न्यायालय केवल इस आधार पर मध्यस्थ पुरस्कार को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता है कि मध्यस्थ ने कानून या तथ्य की कोई गलती की हो सकती है " [करहा बोडास कंपनी एलएलसी बनाम पेरुसाहान पर्टबांगन मिन्याक डैन गैस बुमी नेगारा, 364 एफ.3 डी 274, 287-88 (5 सर्किल 2004)]। इस प्रकार, लक्ज़मबर्ग सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में [24 नवंबर 1993 का निर्णय, XXI Y.B. Comm. Arb. 617, 623 (लक्ज़मबर्ग कोर्ट सुप्रीयर डी जस्टिस) (1996)]:

> "न्यू यॉर्क कन्वेंशन मध्यस्थों द्वारा योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के तरीके पर कोई नियंत्रण प्रदान नहीं करता है, केवल एक आरक्षण के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति का सम्मान करता है। यहां तक कि अगर स्पष्ट रूप से, तथ्य या कानून की गलती, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है, तो न्यायाधिकरण के फैसले को लागू करने से इनकार करने का आधार नहीं है।"

या, कन्वेंशन के तहत ब्राजील के मान्यता निर्णय के रूप में [19 अगस्त 2009 का निर्णय, एटेक्स मैनेसमैन जीएमबीएच बनाम। रोड्रीमर एस/ए ट्रांसपोर्ट औद्योगिक उपकरण और गोदाम जनरल, XXXV वाई.बी. कम्यूनिटी अर्ब. 330, 331 (ब्राजील न्यायालय न्याय) (2010)]:

> “ये प्रश्न मध्यस्थ पुरस्कार की योग्यता से संबंधित हैं, जो कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संघीय सर्वोच्च न्यायालय और इस सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस के उदाहरणों के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है क्योंकि विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन पुरस्कार की औपचारिक आवश्यकताओं के विश्लेषण तक सीमित है।"

टिप्पणीकारों ने कन्वेंशन के बारे में समान रूप से एक ही दृष्टिकोण अपनाया है [उदाहरण के लिए, के.-एच. बोकस्टीगल, एस. क्रोल और पी. नैसिमिएंटो, आर्बिट्रेशन इन जर्मनी 452 (2007) देखें]।" (पृष्ठ 3707-3710 पर)

(जोर दिया गया)

48. इसी तरह, विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन पर UNCITRAL सचिवालय गाइड (न्यूयॉर्क, 1958) (2016 संस्करण) ["न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर UNCITRAL गाइड"] में भी कहा गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "9. अनुच्छेद V के तहत इनकार करने के आधार में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा कानून या तथ्य में गलत निर्णय शामिल नहीं है। कन्वेंशन के तहत मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन के साथ जब्त की गई अदालत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय की योग्यता की समीक्षा नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर केस लॉ और टिप्पणी में सर्वसम्मति से पुष्टि की गई है।"

69. इसलिए हम उपरोक्त अधिकारियों का अनुसरण करते हुए मानते हैं कि अनुबंध की गलत व्याख्या और उसके परिणामस्वरूप "अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों" की आड़ में, यह कहना संभव नहीं है कि मध्यस्थ पुरस्कार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर होगा यदि अन्यथा उपरोक्त गलत व्याख्या (जिसमें अनुबंध की शर्तों से परे जाना शामिल होगा) को मध्यस्थता समझौते के भीतर "विवाद" के रूप में उचित रूप से समझा जा सकता है, या जिसे मध्यस्थों के निर्णय के लिए संदर्भित किया

गया था जैसा कि उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समझा गया था। यदि किसी मध्यस्थ पर अनुबंध से बाहर जाने और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटने का आरोप है, तो यह एक अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि होगी जिसे "पेटेंट अवैधता" के आधार पर ठीक किया जा सकता है, जो, जैसा कि हमने देखा है, 1996 अधिनियम के भाग II के तहत तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू नहीं होगा। 1996 के अधिनियम की धारा 28(3) से संबंधित पिछले दरवाजे से मामले को धारा 34(2)(ए)(iv) के तहत मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर लाना स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि इस आधार को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए और इस तरह से समझा जाना चाहिए कि केवल उन मामलों को संदर्भित किया जाना चाहिए जो मध्यस्थता समझौते से परे हैं या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के संदर्भ से परे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि विदेशी पुरस्कार लागू करने योग्य है, तो पुरस्कार को उस न्यायालय का निर्णय माना जाएगा और न्यायालय को विदेशी पुरस्कार को उस न्यायालय के निर्णय के रूप में निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अंत में, वह प्रस्तुत करेगी कि प्रतिवादी/निर्णय ऋणी द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ संधारणीय नहीं हैं। इसलिए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दोनों आवेदनों को स्वीकार करने और प्रवर्तन के लिए पुरस्कारों को मान्यता देने का अनुरोध किया है।

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया।

12. अधिनियम, 1996 की धारा 48 में वे आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर विदेशी पुरस्कार को अस्वीकार किया जाता है। उक्त धारा नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

48. विदेशी पंचाट के प्रवर्तन की शर्तें। (1) किसी विदेशी पंचाट

के प्रवर्तन से उस पक्षकार के अनुरोध पर इनकार किया जा सकता है जिसके विरुद्ध उसका आह्वान किया गया है , केवल तभी जब वह पक्षकार न्यायालय को यह प्रमाण प्रस्तुत कर दे कि-

(क) धारा 44 में निर्दिष्ट करार के पक्षकार, उन पर लागू कानून के अधीन, किसी अक्षमता के अधीन थे , या उक्त करार उस कानून के अधीन वैध नहीं है जिसके अधीन पक्षकारों ने इसे किया है, या, उस पर कोई संकेत न मिलने पर, उस देश के कानून के अधीन वैध नहीं है जहां यह पंचाट किया गया था; या

(ख) जिस पक्ष के विरुद्ध निर्णय दिया गया है, उसे मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की समुचित सूचना नहीं दी गई थी या वह अन्यथा अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था; या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) यह निर्णय किसी ऐसे मतभेद से संबंधित है जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाने की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है या उसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाने की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं:

बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को उन मामलों से अलग किया जा सकता है जो इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो पंचाट का वह भाग जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णय शामिल हैं, लागू किया जा सकता है; या

(घ) मध्यस्थ प्राधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं थी , या, ऐसे समझौते में विफल होने पर, उस देश के कानून के अनुसार नहीं थी जहाँ मध्यस्थता हुई थी;

या

(ई) निर्णय अभी तक पक्षों पर बाध्यकारी नहीं हुआ है, या उस देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित कर दिया गया है जिसमें या जिसके कानून के तहत वह निर्णय दिया गया था।

(2) मध्यस्थता निर्णय के प्रवर्तन से भी इनकार किया जा सकता है यदि न्यायालय पाता है कि-

(क) मतभेद का विषय-वस्तु भारत के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान योग्य नहीं है; या

(ख) इस निर्णय का प्रवर्तन भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

[स्पष्टीकरण 1. किसी भी संदेह से बचने के लिए , यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई पंचाट भारत की सार्वजनिक नीति के साथ तभी संघर्ष में है, जब- (i) पंचाट का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था; या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन करता है; या

(iii) यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ संघर्ष में है।

स्पष्टीकरण 2 - संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मूल नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।]

(3) यदि निर्णय को रद्द करने या निलंबित करने के लिए आवेदन उपधारा (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को किया गया है, तो न्यायालय, यदि वह इसे उचित समझता है, निर्णय के प्रवर्तन पर निर्णय स्थगित कर सकता है और निर्णय के प्रवर्तन का दावा करने वाले पक्ष के आवेदन पर , दूसरे पक्ष को उपयुक्त सुरक्षा देने का आदेश भी दे सकता है।

13. प्रतिवादी/निर्णय-ऋणी के विद्वान अधिवक्ता ने केवल एक विशिष्ट दलील दी है कि उक्त पुरस्कार इस आधार पर लागू करने योग्य नहीं हैं कि वे भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत हैं। कोविड -19 महामारी की स्थिति को विषय अधिसूचना में संदर्भित किया गया है जो अधिनियम, 2005 के तहत जारी की गई है। विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 (विदेशी पुरस्कार अधिनियम) में निहित अभिव्यक्ति "भारत की सार्वजनिक नीति" की व्याख्या **रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, 1994 सप. (1) एससीसी 644 (रेनुसागर)** में की गई थी। उक्त अभिव्यक्ति को विदेशी पुरस्कार के संदर्भ में उक्त निर्णय में एक संकीर्ण निर्माण प्राप्त हुआ। मध्यस्थता अधिनियम के अधिनियमित होने और परिणामस्वरूप विदेशी पुरस्कार अधिनियम के निरस्त होने के पश्चात, मध्यस्थता अधिनियम में निहित अभिव्यक्ति "भारत की सार्वजनिक नीति" का उचित निर्माण **श्री लाल महल लिमिटेड (सुप्रा)** में तय किया गया था। उक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह सार्वजनिक नीति का संकीर्ण निर्माण है जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 की व्याख्या पर लागू होना चाहिए। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एलीमेंटा एस.ए. (सुप्रा)** में विदेशी पुरस्कार को लागू करने योग्य घोषित करने से इनकार कर दिया, उक्त निर्णय भारत सरकार द्वारा नेफेड को प्रासंगिक वस्तु के निर्यात की अनुमति देने से इनकार करने के संदर्भ में दिया गया था। इस आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन भारत की मौलिक नीति और न्याय की बुनियादी धारणाओं का उल्लंघन होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई विदेशी निर्णय भारतीय कानून की मूल नीति या नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के विपरीत न हो, उसे मान्यता दी जानी चाहिए और लागू किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह प्रश्न कि क्या विदेशी पंचाट के किसी भाग की मान्यता और प्रवर्तन, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में सार्वजनिक

नीति के विपरीत है, एक अलग और विशिष्ट मामला है। अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति" को सीधे-सीधे नहीं रखा जा सकता। जैसा कि **रेनूसागर** और बाद में **श्री लाल महल (सुप्रा)** में व्याख्या की गई है, उक्त अभिव्यक्ति को विदेशी पंचाट के संदर्भ में एक संकीर्ण व्याख्या प्राप्त करने की आवश्यकता है।

15. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर वापस लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की स्थिति में , हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमेबाजी के मामलों में संज्ञान के लिए सीमा बढ़ा दी है, लेकिन उक्त अधिसूचना में ही बैंकों और अन्य संगठनों के लिए एक अपवाद है और उक्त आपत्ति विद्वान मध्यस्थों के समक्ष उठाई गई है। विद्वान मध्यस्थों ने उक्त मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विस्तार से विचार किया है और पाया है कि बैंक और शिपिंग अपवादित उद्योग हैं और वे लॉकडाउन नियमों के अधीन नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यदि प्रतिवादी/न्यायिक देनदार के विद्वान अधिवक्ता की दलील को स्वीकार भी कर लिया जाता है , तो भी सुविधा के लिए ऐसी आकस्मिकताओं में कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। संबंधित अवधि के दौरान, संबंधित व्यक्ति सक्षम अधिकारियों की अनुमति/परमिट प्राप्त करने के बाद बैंक से संपर्क कर सकता था। बैंकिंग क्षेत्र ने ऐसी असाधारण परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है ताकि किसी भी वित्तीय कठिनाई से बचा जा सके। विद्वान मध्यस्थों ने उक्त आपत्ति को खारिज करने के लिए ठोस कारण बताए हैं। इसलिए, इस तरह के आधार पर दिए गए पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत या उसके विरुद्ध नहीं होंगे और प्रतिवादी/न्यायिक देनदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई उक्त आपत्ति संधारणीय नहीं है।

17. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, आवेदक यह घोषित करने वाले आदेश का हकदार है कि विदेशी पुरस्कार को मान्यता प्राप्त है और परिणामस्वरूप, इस न्यायालय के आदेश के रूप में लागू किया जा

सकता है। यदि भुगतान नहीं किया गया है , तो आवेदक के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के लागू प्रावधानों के अनुसार उपायों का सहारा लेकर विदेशी पुरस्कार को लागू करना खुला है।

18. परिणामस्वरूप, दोनों मध्यस्थता आवेदनों को उपरोक्त शर्तों पर बिना किसी लागत के आदेश के अनुमति दी जाती है।

एसडी/-

(दीपक कुमार तिवारी)

न्यायाधीश

श्याना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>एआरबीएपी संख्या 10 वर्ष 2023 और एआरबीएपी संख्या 9 वर्ष 2023</u>

<u>शीर्ष टिप्पणी</u>

विदेशी पुरस्कार प्रवर्तन - कोविड-19 महामारी के दौरान भी बैंकिंग क्षेत्र ने आवश्यक सेवाएं प्रदान करना जारी रखा और अधिसूचना में उक्त क्षेत्र अपवाद के अंतर्गत है, इसलिए पुरस्कार को भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं कहा जा सकता। विदेशी पुरस्कार को न्यायालय के आदेश के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे लागू किया जा सकता है।

विदेशी अवार्ड का प्रवर्तन & कोविड १९ महामारी के दौरान भी बैंकिंग क्षेत्र ने निरन्तर आवश्यक सेवाए प्रदान की जाती है तथा अधिसूचना में उक्त क्षेत्र छूट के अंतर्गत, ताकि अवार्ड को भारत के लोक नीति के प्रतिकूल न समझा जावे। विदेशी अवार्ड न्यायालय के डिक्री के समान मान्यता प्राप्त और प्रवतर्नीय है।

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur